PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ▸ Issue : 1 ▸ Mumbai ▸ Friday, 6 February to 12 February 2026 ▸ Weekly ▸ Pages: 8 ▸ Price : 3 Rs.

महाराष्ट्र सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 20,400 एकड़ से अधिक भूमि का किया अधिग्रहण

इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी जमीन अधिग्रहण तेजी से पूरा किया जाए – मुख्यमंत्री

मुंबई - राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 20,431 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों के पास 8,969 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में औद्योगिक निवेश की भारी मांग है और उद्यमियों द्वारा अधिग्रहित भूमि को देखते हुए उन्होंने एमआईडीसी को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुंबई, पुणे और नागपुर के साथ-साथ नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और सोलापुर जैसे क्षेत्रों में भी निवेशकों द्वारा भूमि की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

विभिन्न जिलों में एमआईडीसी के भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ, मुख्यमंत्री ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, विरार-अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर, नागपुर-गोंडिया एक्सप्रेसवे, भंडारा-गडचिरोली एक्सप्रेसवे, नागपुर-चंद्रपुर एक्सप्रेसवे, नवेगांव-सूरजगढ़

मिनरल कॉरिडोर और जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे जैसी एमएसआरडीसी परियोजनाओं की चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की भी समीक्षा की।

फडनाविस ने कहा कि राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं को तीन साल में पूरा करने की योजना बनाई जानी चाहिए। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए। साथ ही, अधिक से अधिक ऐसे निकटवर्ती क्षेत्रों से भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए जो वन क्षेत्र न हों और उद्यमियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा, विभिन्न विभागों से सरकारी भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे उद्यमियों को कम दरों पर भूखंड उपलब्ध होंगे और राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि कोंकण में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान कहीं भी वन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया।

कैंसर की शुरूआती जांच के लिए 'आशा वन' का शुभारंभ

गांधीनगर - गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गांधीनगर में मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट 'आशा वन' का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में कैंसर की प्रारंभिक पहचान, त्वरित जांच और समय पर उपचार को सुलभ बनाना है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों के नागरिकों के लिए।

'आशा वन' एक अत्याधुनिक चलित चिकित्सा इकाई है, जिसे नवीनतम स्वास्थ्य तकनीकों से सुसज्जित किया गया है। इसमें EVA-Pro डायग्नोस्टिक सिस्टम, मैमोग्राफी यूनिट तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से टेली-परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। इस मोबाइल यूनिट के माध्यम से मौके पर ही कैंसर सहित कई गंभीर एवं जानलेवा बीमारियों की जांच और प्राथमिक निदान किया जा सकेगा। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल

ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में समय पर पहचान और जांच से उपचार की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 'आशा वन' जैसी मोबाइल इकाइयाँ स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों की दहलीज तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह यूनिट राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर नियमित रूप से स्क्रीनिंग करेगी, जिससे आम नागरिकों को बिना बड़े अस्पतालों में जाए ही प्रारंभिक जांच की सुविधा मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि यह पहल राज्य में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। यह परियोजना निवारक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में गुजरात सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

केंद्र सरकार की 'राह-वीर' योजना लागू

हादसे में मदद करें, पाएं रु. 25,000 का इनाम

नई दिल्ली - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुँचाने के लिए 'राह-वीर' योजना शुरू की है। योजना के तहत गोल्डन आवर में घायल को अस्पताल पहुँचाने वाले नागरिक को रु. 25,000 नकद पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा, जब इलाज मिलने पर जान बचने की संभावना सबसे अधिक होती है।

उद्देश्यः अधिक से अधिक लोग आगे आकर घायल की जान बचाने में मदद करें।

योजना की मुख्य बातें:

- मददगार को रु.25,000 नकद पुरस्कार
- प्रशस्ति पत्र व सरकारी सम्मान
- कानूनी पूछताछ से सुरक्षा
- पहचान गोपनीय रखने का विकल्प
- गुड समैरिटन नियमों के तहत संरक्षण

बदलापुर में अनधिकृत निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

बदलापुर - जनवरी 2026 में बदलापुर नगरपालिका ने शहर में बढ़ते अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत मुख्य सड़कों, हाईवे किनारे और सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध ढांचे और निर्माण को ध्वस्त किया गया। नगरपालिका ने बताया कि यह कार्रवाई शहर की नियोजित विकास योजना और सार्वजनिक हित की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

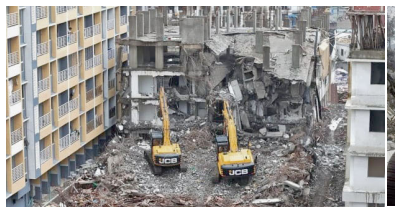

नगर प्रशासन ने अभियान शुरू करने से पहले सूचना और चेतावनी जारी की। स्थानीय कर्मचारियों और पुलिस की सहायता से अवैध निर्माण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक संपत्ति और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा गया।

इस कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और प्रशासन पर पक्षपात के आरोप भी लगाए। हालांकि, नगरपालिका ने स्पष्ट किया कि यह कदम सार्वजनिक हित और कानून के अनुसार उठाया गया है, न कि किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक हित के लिए।

बदलापुर तेजी से बढ़ता औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण न केवल यातायात और नगर नियोजन को प्रभावित करता है, बल्कि सुरक्षा और नागरिक जीवन के लिए भी खतरा बन जाता है। यह अभियान शहर की साफ-सुथरी और व्यवस्थित छवि बनाए रखने में मदद करेगा। भविष्य में नियमित निगरानी और सख्त कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करेगा कि कोई भी अनधिकृत निर्माण नए शहर नियोजन मानकों का उल्लंघन न करे। बदलापुर में जनवरी 2026 की यह कार्रवाई दशार्ती है कि नगर प्रशासन कानून और सार्वजनिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह अभियान केवल अवैध निर्माण को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शहरी नियोजन, यातायात सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा के लिए एक संदेश भी है। भविष्य में ऐसे कदमों से शहर के नियोजित विकास और व्यवस्थित विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार, बदलापुर में चलाया गया यह अभियान कानून, सुरक्षा और शहर नियोजन के संतुलन का प्रतीक है।

कार्रवाई के उद्देश्य

यातायात बाधाओं को दूर करना

- अवैध निर्माण सड़क पर अतिक्रमण करते हैं, जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित होता है। अभियान के माध्यम से मुख्य सड़कों और हाईवे की क्षमता पुनः बहाल की गई।

नियोजित विकास योजना को लागू करना

- शहर की मास्टर प्लान और नियोजन के अनुसार निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करना। नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी ध्वस्त किए गए ढांचे कानून के दायरे में थे।

भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकना

- अवैध निर्माण अक्सर सुरक्षा खतरे पैदा करते हैं। बिजली, पानी और आपातकालीन मार्गों पर अतिक्रमण के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है।

प्यूपिल्स टाइम्स

संपादकीय

भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत

पहले यूरोपीय संघ के साथ बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर और उसके कुछ ही दिनों के भीतर अमेरिका के साथ एक तरह के व्यापार युद्ध में संघर्षविराम की स्थिति निःसंदेह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। उनके लिए नए साल की इससे बेहतर शुरूआत शायद ही हो सकती थी। खास तौर से तब जब पिछला साल कूटनीतिक तनाव, आपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध की आशंका और अमेरिका के साथ खटपट के नाम रहा। इस संदर्भ में अमेरिका के साथ बिगड़ी हुई बात का बनना बहुत कुछ कहता है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत के टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय मात्र एक आर्थिक राहत नहीं है, बल्कि यह मोदी की विदेश नीति की महत्वाकांक्षा और दृढ़ता की पुष्टि भी है। जब तमाम विश्लेषक यह मान बैठे थे कि ट्रंप 2.0 के दौर में भारत को लगातार दबाव और अपमान झेलना पड़ेगा, उसी दौरान मोदी ने धैर्य, रणनीति और आत्मविश्वास के साथ स्थिति को पलट दिया। यह समझौता दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। देखा जाए तो मोदी ने वह कर दिखाया जो तमाम वैश्विक नेता नहीं कर सके। मोदी ने ट्रंप की कुख्यात 'द आर्ट आफ द डील' रणनीति को समझा और उसे भारत के हित में साध लिया। ट्रंप की सौदेबाजी बेहद आक्रामक, दबाव बनाने वाली और अतिरंजित दावों पर आधारित रही है। कनाडा, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी भी उनकी इस शैली के सामने अक्सर रक्षात्मक स्थिति में दिखे। स्वयं भारत ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक सीमित व्यापार समझौते की कोशिश में विफल रहा था, लेकिन इस बार मोदी ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही आत्मसमर्पण किया। उन्होंने ट्रंप को वह राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की गुंजाइश दी, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति व्यग्र थे। जबकि वास्तविक लाभ भारत के खाते में गया। यह मोदी की कूटनीतिक परिपक्वता और आत्मविश्वास का प्रमाण है। टैरिफ कटौती के बीच ट्रंप ने एकतरफा दावे भी किए। जैसे भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देगा। भारत अमेरिकी उत्पादों की 500 अरब डालर तक की खरीद करेगा और अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं शून्य कर देगा। ये दावे जितने नाटकीय हैं, उतने ही अव्यावहारिक भी प्रतीत होते हैं। भारत का अमेरिका से कुल वार्षिक आयात करीब 50 अरब डालर से भी कम है। 500 अरब डालर का आंकड़ा नीति से अधिक राजनीतिक नारेबाजी जैसा अधिक है। कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत का पूर्ण उदारीकरण घरेलू राजनीति और सामाजिक स्थिरता के लिहाज से वैसे भी असंभव है। मोदी का इन बिंदुओं पर मौन रहना दशार्ता है कि भारत इस समझौते को एक दिशात्मक संकेत के रूप में देख रहा है, न कि अंतिम और बाध्यकारी समझौते के रूप में। अपने स्वरूप में यह घटनाक्रम किसी ठोस समझौते से अधिक एक राजनीतिक ब्रेकथ्रू है। यह ट्रंप प्रशासन की उसी प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसमें पहले बड़े एलान किए जाते हैं और बाद में विवरण तय होते हैं। अतीत में यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के साथ भी ऐसे फ्रेमवर्क समझौतों की घोषणा हुई, जिनका क्रियान्वयन जटिल और लंबा साबित हुआ।

सूफी बसंत : सात सौ पचास वर्षों से बहता प्रेम, संगीत और साझी विरासत का उत्सव

हैदराबाद - जब बसंत की हवा रंग और उल्लास लेकर आती है, तब हैदराबाद की धरती पर एक ऐसी परंपरा जीवित हो उठती है, जो समय, सीमाओं और पहचान की दीवारों से परे जाकर मानवता की बात करती है। यह परंपरा है सूफी बसंत, जिसकी जड़ें लगभग 750 वर्ष पूर्व दिल्ली के महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया और उनके शिष्य अमीर खुसरो से जुड़ी हुई हैं।

इस वर्ष भी हैदराबाद में यह परंपरा श्रद्धा और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाई गई। आयोजन तेलंगाना आर्ट्स एंड कल्चरल काउंसिल के सहयोग से संपन्न हुआ, जबकि इसकी निरंतरता का श्रेय मुख्य आयोजक श्री मुजफ़्फर बेग को जाता है, जो वर्ष 2014 से इस आयोजन को हैदराबाद में आयोजित करते आ रहे हैं।

सूफी बसंत की उत्पत्ति एक करुण प्रसंग से जुड़ी है। इतिहास के अनुसार, अपने भतीजे की मृत्यु के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया गहरे शोक में डूब गए थे। उस समय अमीर खुसरो ने बसंत के गीत, पीले रंग और संगीत के माध्यम से उन्हें सांत्वना दी। यहीं से बसंत को सूफी परंपरा में शोक को प्रेम में बदलने वाले उत्सव के रूप में स्थान मिला। यह परंपरा समय के साथ केवल धार्मिक नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक और मानवीय उत्सव के रूप में विकसित होती चली गई।

हैदराबाद में आयोजित सूफी बसंत महोत्सव की प्रमुख प्रस्तुति रही 'मेहफि ल-ए-निजामी'। इस संगीतमय संध्या में सूफी कव्वाली परंपरा से जुड़े वरिष्ठ कलाकारों ने अमीर खुसरो की चयनित रचनाओं को स्वर दिया।

कव्वाली यहाँ केवल संगीत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बनकर उभरी। श्रोता केवल दर्शक नहीं रहे, बल्कि भावनात्मक रूप से उस यात्रा का हिस्सा बने, जहाँ शब्द, स्वर और साधना एक हो जाते हैं। इस उत्सव में शामिल हुए, जिसने इसकी समावेशी प्रकृति को और सुदृढ़ किया। श्री मुजफ्फर बेग के नेतृत्व में आयोजित यह सूफी बसंत महोत्सव केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए एक सांस्कृतिक संदेश और भविष्य के लिए एक दिशा है। यह आयोजन सिद्ध करता है कि संगीत और अध्यात्म आज भी समाज को जोड़ने की शक्ति रखते हैं। सूफी बसंत एक उत्सव नहीं, बल्कि एक सतत संवाद है–मनुष्य और मनुष्य के बीच।

■ अतिथि और सहभागिता

इस आयोजन में तेलंगाना आर्ट्स एंड कल्चरल काउंसिल के प्रतिनिधि, सूफी संगीत एवं सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े वरिष्ठ कलाकार, साहित्य, इतिहास और संस्कृति से जुड़े विद्वान विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन को औपचारिक राजनीतिक मंच न बनाते हुए इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप में ही रखा गया।

■ हैदराबाद की साझा संस्कृति का प्रतिबिंब

हैदराबाद लंबे समय से गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक रहा है। सूफी बसंत महोत्सव इसी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाता है। यहाँ धर्म पहचान नहीं बनता, बल्कि संगीत और संवेदना साझा सूत्र बनते हैं।

■ समकालीन संदर्भ में महत्व

आज के समय में, जब समाज में विभाजन की रेखाएँ उभरती दिखाई देती हैं, सूफी बसंत जैसी परंपराएँ यह याद दिलाती हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल संवाद, सह-अस्तित्व और प्रेम में निहित है।

केरल में देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायपालिका की शुरूआत

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

वायनाड (केरल) - भारत ने न्यायिक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायपालिका का शुभारंभ किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत ने केरल के वायनाड ज़िले के कल्पेट्टा में इस व्यवस्था का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।

इस पहल के साथ ही पहली बार देश में किसी पूरे ज़िले की न्यायालय प्रणाली ने एंड-टू-एंड डिजिटल कार्यप्रणाली को अपनाया है, जिसे न्याय तक आसान, पारदर्शी और त्वरित पहुँच की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है।

कल्पेट्टा ज़िले के सभी न्यायालय अब पूरी तरह डिजिटल रूप से संचालित हो रहे हैं। इसमें ई-फाइलिंग, डिजिटल स्क्रूटनी, और मामलों से संबंधित सूचनाओं तक त्वरित ऑनलाइन पहुँच की सुविधा शामिल है। यह समस्त व्यवस्था जिला न्यायालय केस प्रबंधन प्रणाली के माध्यम

से संचालित की जा रही है, जिसे केरल उच्च न्यायालय द्वारा इन-हाउस विकसित किया गया है। न्यायिक अधिकारियों के अनुसार, इस डिजिटल प्रणाली से न केवल कागजी कार्यवाही में कमी आएगी, बल्कि मामलों के निस्तारण में भी तेजी आएगी। साथ ही, वादकारियों और अधिवक्ताओं को अदालतों के चक्कर काटने की आवश्यकता कम होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत ने अपने संबोधन में कहा कि यह पहल डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप है और न्याय प्रणाली को अधिक सुलभ, दक्ष एवं पर्यावरण-अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि केरल का यह मॉडल भविष्य में देश के अन्य राज्यों के लिए एक मानक (मॉडल) व्यवस्था बन सकता है और भारतीय न्याय प्रणाली को आधुनिक तकनीक से सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

अब डिजिटल एटीवीएम से कतारें कम होंगी

वेस्टर्न रेलवे स्टेशन परिसर में 325 डिजिटल एटीवीएम

मुंबई - मुंबईकरों के लिए ट्रेन टिकट पाना अब और तेज और आसान होने वाला है। वेस्टर्न रेलवे ने सबअर्बन रेलवे लाइनों पर 325 नई ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें (एटीवीएम) लगाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि इस पहल से टिकट खिड़कियों पर लंबी लाइनें कम होंगी और यात्रियों को डिजिटल के साथ-साथ सेल्फ-सर्विस टिकटिंग का ऑप्शन मिलेगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, नई ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनें स्टेशन परिसर के साथ-साथ फुट ब्रिज पर भी लगाई जाएंगी, जिससे भीड़-भाड़ वाले समय में यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ये मशीनें पहले से ज्यादा तेज काम करेंगी और UPI समेत कई डिजिटल पेमेंट ऑप्शन देंगी। मेरा टिकट, मेरी शान - मेरा गढ़ आत्मनिर्भर भारत के लिए कैंपेन के तहत चर्चगेट स्टेशन पर यह पहल शुरू की गई। इस कैंपेन का उद्घाटन वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर-इन-चार्ज प्रदीप कुमार ने किया। प्रदीप कुमार ने कहा, हर यात्री जो वैलिड टिकट के साथ यात्रा करता है, वह सीधे तौर पर रेलवे के मॉडर्नाइजेशन और देश बनाने में योगदान देता है। इसलिए, यात्रियों को हमेशा वैलिड टिकट के साथ यात्रा करनी चाहिए।

कैसे और क्या फायदा होगा?

नई एटीवीएम में यूपीआय और दूसरे डिजिटल पेमेंट मोड होंगे, जिससे यात्रियों को कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, रेलवे ने फ्रं डल्ली मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए यात्री अब सीधे अपने मोबाइल फोन से टिकट बुक कर सकते हैं।

अभी, वेस्टर्न रेलवे रूट पर 501 ATVM चल रही हैं। इनमें से 110 मशीनों की सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद उन्हें बदल दिया जाएगा। बाकी मशीनों को यात्रियों की सुविधा के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले, यात्री अक्सर ATVM के बंद होने, रश आवर्स में उपलब्ध न होने और मशीनों के खराब होने की शिकायत करते थे। हालांकि, नई मशीनें ज्यादा भरोसेमंद होंगी और टिकट काउंटर पर निर्भरता कम करेंगी।

प्यूपिल्स टाइम्स

29 शहरों के मेयर पद का आरक्षण तय

मुंबई, नवी मुंबई, पुणे समेत 15 नगर निगमों को मिलेंगी महिला मेयर

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबई - मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों में महापौर पदों के लिए 'लॉटरी' निकाली गई। यह काम राज्य सचिवालय (मंत्रालय) में किया गया। इसमें मुंबई में मेयर का पद सामान्य महिला कैटेगरी के लिए आरक्षित किया गया है। मुंबई के अलावा नवी मुंबई में सामान्य महिला, मीरा भयंदर-सामान्य, पुणे सामान्य महिला, पिंपरी चिंचवाड़ सामान्य महिला, भिवंडी सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। वहीं नासिक, नागपुर, संभाजीनगर, अमरावती, वसई विरार, परभणी, नांदेड़, सांगली, मालेगांव, सोलापुर, धुले में सामान्य श्रेणी के महापौर होंगे। आइए जानते हैं मेयर पद की लॉटरी से जुड़े हर अपडेट?

अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में असल में किसकी सरकार बनेगी? इस पर भले ही बहस हो रही हो, लेकिन कांग्रेस

अकोला में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी यहां सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच कांग्रेस विधायक साजिद खान पठान ने आज अकोला में वंचितों के नेता प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। दूसरी ओर शरद पवार और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की, जिससे चर्चाओं को हवा मिली है। इस बीच, कांग्रेस पहले ही हमसे कोई पद नहीं बल्कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने की अपील कर चुकी है। इन सभी डेवलपमेंट के बाद अंबेडकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल सुबह 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी।

इस बार मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में महिलाओं का राज होगा। सामान्य कैटेगरी रिजर्वेशन ड्रॉ शुरू हो गया है और इन चार सबसे जरूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महिलाओं का राज होगा।

वाई-फाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम

500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बिना लाइसेंस इस्तेमाल की अनुमति

मुंबई - देश में वाई-फाई सेवाओं को तेज और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग (डॉट) ने 6 गीगाहर्ट्ज बैंड के निचले हिस्से में मौजूद 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को बिना लाइसेंस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से घरों, दफ्तरों और सार्वजनिक जगहों पर वाई-फाई की गति और क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

डॉट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 5925 से 6425 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज का इस्तेमाल अब कम पावर इनडोर और बहुत कम पावर वाले आउटडोर वाई-फाई सिस्टम के लिए किया जा सकेगा। इसके लिए किसी तरह का लाइसेंस या स्पेक्ट्रम आवंटन लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी वाई-फाई उपकरण बिना सरकारी अनुमति के इस स्पेक्ट्रम पर काम कर सकेंगे। सरकार ने यह फैसला करीब छह महीने पहले जारी किए गए मसौदा नोटिफिकेशन के बाद लिया है। हालांकि, इस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसका उपयोग साझा आधार पर होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी अन्य संचार सेवा में बाधा न पड़े। सिग्नल की शक्ति पर भी सीमा रखी गई है, ताकि इसका इस्तेमाल केवल वाई-फाई जैसे कम पावर वाले उपकरणों तक ही सीमित रहे।

डॉट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का ऊपरी हिस्सा भविष्य में मोबाइल सेवाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इससे वाई-फाई और मोबाइल नेटवर्क के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। टेलीकॉम और आईटी क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से वाई-फाई 7 जैसी नई तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।

अब विदेश से ज्यादा सामान और गहने ला सकेंगे भारतीय

सरकार ने बढ़ाई ड्यूटी-फ्री लिमिट

प्यूपिल्स टाइम्स संवाददाता

मुंबई - सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए ड्यूटी-फ्री सामान की सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने रविवार को भारत में ड्यूटी-फ्री आयातित सामान लाने वाले यात्रियों के लिए सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। इस फैसले से यात्रियों को ज्यादा सहूलियत मिलेगी और यात्रा के दौरान की गई खरीदारी पर आर्थिक बोझ भी कम होगा।

न्यूज एजेंसी के अनुसार, रविवार को अधिसूचित बैगेज नियम, 2026 के तहत, भारत में जमीन के रास्ते के अलावा किसी अन्य रास्ते से आने वाले भारतीय मूल के निवासी या पर्यटक को 75,000 रुपये तक के सामान पर ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस की अनुमति होगी, यदि ऐसा सामान यात्री अपने साथ या अपने असली सामान में ला रहा है।

नए बैगेज नियम, 2026, 2 फरवरी यानी आज से लागू हो गया है। इस नियम ने दशक पुराने बैगेज नियम की जगह ले लिया है। अब भारत आने वाले विदेशी मूल के पर्यटक, जो शिशु नहीं हैं, उन्हें 25,000 रुपये तक के सामान पर ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस की अनुमति होगी। बैगेज नियम, 2016 में यह सीमा 15,000 रुपये थी। यदि कोई निवासी या भारतीय मूल का पर्यटक 1 साल से अधिक समय से विदेश में रह रहा है, तो भारत लौटने पर, उसे 40 ग्राम वजन तक के गहनों पर ड्यूटी-फ्री क्लीयरेंस की अनुमति होगी, यदि इसे कोई महिला यात्री ला रही है। यदि कोई महिला यात्री के अलावा कोई और व्यक्ति असली सामान में लाता है तो यह सीमा 20 ग्राम होगी।

इस नियम के प्रयोजन के लिए, गहने का मतलब सोने, चांदी, प्लैटिनम या ऐसी अन्य कीमती धातुओं से बनी सजावट की वस्तुएं हैं, जिन्हें आमतौर पर कोई व्यक्ति पहनता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अप्रैल डिलीवरी के लिए सोने का फ्यूचर कमजोर शुरूआत के साथ खुला और शुरूआती कारोबार में 10,688 रुपये या 7.2 प्रतिशत गिरकर 10 ग्राम पर 1,37,065 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया।

रिकॉर्ड हाई से रिवर्स गियर!

सोमवार को फ्यूचर ट्रेड में सोने की कीमतें शुरूआती तेज गिरावट के बाद 10 ग्राम पर 1.48 लाख रुपये तक रिकवर हो गईं, जिससे लोअर सर्किट लेवल ट्रिगर हो गया, जबकि चांदी में लगातार तीसरे दिन भारी बिकवाली देखी गई और नुकसान जारी रहा।

अगर आप पांच बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं, तो आपका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा

राज्य सरकार का गाड़ी मालिकों को बड़ा झटका

मुंबई - सड़कों पर गाड़ियां चलाने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हर वाहन चालक के लिए जरूरी होता है. इन्हें नजरअंदाज करने पर न सिर्फ भारी जुर्माना लगता है. बल्कि कई मामलों में सजा तक का प्रावधान है. इन नियमों का मकसद है सड़कें सुरक्षित रहें और लोग जिम्मेदारी से वाहन चलाएं. अब इसी के लिएएक बड़ा बदलाव किया गया है.

Motor Vehicles Rules में बदलाव करते हुए सरकार ने आदतन ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है. नए नियम के तहत अगर कोई ड्राइवर बार बार लापरवाही करता है, तो अब सिर्फ चालान काटकर नहीं छोड़ा जाएगा. सीधे उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई होगी. यह कदम सड़क हादसों पर लगाम लगाने और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति डर और जिम्मेदारी दोनों पैदा करने के लिए उठाया गया है.

मोटर व्हीकल रूल्स में सरकार के नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक साल के भीतर पांच या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है. तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. यानी बार बार ओवरस्पीड, रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाने वाली गलतियां अब सीधे लाइसेंस पर भारी पड़ेंगी. हालांकि कार्रवाई तुरंत नहीं होगी पहले संबंधित ड्राइवर को नोटिस भेजा जाएगा. उसे मौका मिलेगा कि वह अपनी सफाई पेश करे और सबूतों के साथ बताए कि उस पर लगाए गए आरोप गलत हैं या किसी मजबूरी में नियम टूटा. अगर अधिकारी ड्राइवर की बातों से सहमत हो जाते हैं. तो लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा. लेकिन जवाब कमजोर रहा तो तीन महीने तक गाड़ी चलाने पर पूरी तरह रोक लग सकती है. इस नए प्रावधान में सिर्फ पिछले एक साल के अंदर हुए ट्रैफिक उल्लंघन ही गिने जाएंगे. एक साल से पुराने मामलों को इस गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा. इसका मतलब कि हालिया व्यवहार के आधार पर तय होगा कि ड्राइवर आदतन नियम तोड़ने वाला है या नहीं. सरकार ने यह नियम 1 जनवरी से लागू कर दिया है.

प्यूपिल्स टाइम्स

फ्री नहीं रहेगा वाटसऍप.. ?

स्टेटस चलाने के लिए देने होंगे पैसे वरना दिखेंगे विज्ञापन

हम सभी अलग-अलग तरह से स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और सभी के फोन में अलग-अलग ऐप्लिकेशन होती हैं। हालांकि एक ऐसी ऐप जरूर है जो कि हर किसी के फोन में होती है और वह वाटसऍप है। बता दें कि अब जल्द वाटसऍप को इस्तेमाल करना फ्री नहीं रहेगा। दरअसल रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक अब वाटसऍप भी सब्सक्रिप्शन मॉडल लाने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको वाटसऍप पर मैसेज भेजने के लिए पैसे खर्चने होंगे। यह सब्सक्रिप्शन फीचर वाटसऍप के स्टेटस फीचर के लिए आएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मैसेजिंग ऐप में क्या बदलाव हो सकता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वाटसऍप अपने स्टेटस टैब में विज्ञापन लेकर आने वाला है। यूजर्स के विरोध के बावजूद, वाटसऍप इस पर लंबे समय से काम कर रहा है। अब खबर मिली है कि वाटसऍप न सिर्फ अपने

फैसले पर अडिग है बल्कि वह एक सब्सक्रिप्शन प्लान भी पेश कर सकता है। ये तमाम डिटेल्स व्हाट्सएप के नए वर्जन 2.26.3.9 के कोड की जांच करने पर सामने आई हैं। कहने का मतलब है कि भविष्य में वाटसऍप 'पेड एड-फ्री सब्सक्रिप्शन' यानी कि पैसे देकर विज्ञापन हटाने वाला मॉडल पेश कर सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर भविष्य में मैसेज भेजने के लिए वाटसऍप को पैसे नहीं देने होंगे, तो आखिर वाटसऍप सब्सक्रिप्शन में देगा क्या? दरअसल यह सब्सक्रिप्शन प्लान वाटसऍप अपने स्टेटस फीचर के लिए ला रहा है। यानी कि वाटसऍप उन यूजर्स को स्टेटस में विज्ञापन दिखाएगा, जो कि वाटसऍप का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। वहीं जो लोग वाटसऍप के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे चुकाएंगे उन्हें स्टेटस में विज्ञापन देखने को नहीं मिलेंगे। वाटसऍप के आने वाले सब्सक्रिप्शन मॉडल पर अभी वाटसऍप की ओर से ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आई है। वाटसऍप के सब्सक्रिप्शन मॉडल के बारे में फिलहाल उसके एक बीटा वर्जन 2.26.3.9 के कोड से पता चला है। ऐसे में हो सकता है कि वाटसऍप तुरंत अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल पेश न करे लेकिन ऐसा मान कर चला जा सकता है कि वाटसऍप कभी न कभी इस मॉडल को पेश करेगा। बता दें कि वाटसऍप का बिजनेस यूजर्स के लिए एक अलग ऐप मौजूद है। इस ऐप का नाम वाटसऍप बिजनेस है। इस ऐप को वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी तरह का बिजनेस करते हैं। इसके जरिए वे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। गौरतलब है कि वाटसऍप बिजनेस यूजर्स को उनके ऐप में अपना सामान ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन देने का ऑप्शन मिलता है।

40 लाख लोगों को रोजगार का टारगेट

महाराष्ट्र ने किए 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते

मुंबई - दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र ने 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए हैं और अतिरिक्त 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर प्रारंभिक बातचीत पूरी हो चुकी

है. इससे 40 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा. ये जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार (22 जनवरी) को पत्रकारों को दी.

महाराष्ट्र के पत्रकारों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इन समझौतों में 83 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हैं और कुल 18 देशों से महाराष्ट्र में निवेश आ रहा है. उन्होंने बताया, 16 प्रतिशत निवेश विदेशी तकनीकी साझेदारी के माध्यम से है. इन 18 देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, जापान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूएई, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम आदि शामिल हैं. उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा, औद्योगिक, सेवा, कृषि और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में यह निवेश आ रहा है. समझौता ज्ञापनों के वास्तविक क्रियान्वयन की दर 75 प्रतिशत है. पिछले वर्ष किए गए समझौते भी 75 प्रतिशत तक वास्तविक रूप से लागू हो चुके हैं. यह निवेश 3 से 7 वर्षों में वास्तविक रूप से सामने आता है.

सीएम ने ये भी बताया कि एसबीजी, ब्रुकफील्ड, आर्सेलर मित्तल, फिनमैन ग्लोबल, इस्सार, स्कोडा ऑटो, फॉक्सवैगन, एसटीटी टेलिमीडिया, टाटा, अडानी, रिलायंस, जेबीएल, कोका-कोला, बॉश, कैपिटल लैंड, आयरन माउंटेन जैसी अनेक कंपनियों के साथ ये समझौते हुए हैं. कुछ समूह भारतीय हैं, लेकिन उनकी लगभग 165 देशों में निवेश मौजूद है. क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, जीसीसी, डेटा सेंटर्स, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रीन स्टील, शहरी विकास, जहाज निर्माण, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सभी क्षेत्रों में निवेश आया है.

400 मीटर का सफर, टैक्सी वाले वसूले 18000

विदेशी महिला पर्यटक की शिकायत पर अरेस्ट

मुंबई - मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक विदेशी महिला से महज कुछ सौ मीटर की दूरी के लिए भारी भरकम रकम वसूलने का मामला सामने आया है. सहार पुलिस ने इस मामले में टैक्सी चालक देशराज यादव (50) को गिरफ्तार किया है, जिस पर एक अमेरिकी नागरिक से कथित तौर पर 18,000 रुपये यानी करीब 200 अमेरिकी डॉलर की ठगी करने का आरोप है. यह घटना 12 जनवरी की बताई जा रही है, जब पीड़िता अमेरिका से मुंबई पहुंची थी. पुलिस के अनुसार, महिला ने हवाई अड्डे के पास स्थित एक पांच सितारा होटल तक जाने के

लिए टैक्सी ली थी, जो मात्र 400 मीटर की दूरी पर था. आरोप है कि टैक्सी चालक यादव ने महिला को सीधे होटल ले जाने के बजाय अंधेरी (पूर्व) इलाके में करीब 20 मिनट तक इधर-उधर घुमाया. इसके बाद उसी इलाके में वापस लाकर उसे होटल पर छोड़ा और बदले में 18,000 रुपये वसूल लिए.

आओ खेलों...

1			5		4			9	3		E		G	7	A
	E		7		9	1		F		A	6	2	4		D
G	6	4	B				E	D	8		2	9		3	
F									C	5		B		1	
	5		C			D		B	2		9	8			
B	8			5	7				F	C					G
A			9	8			1	G	E		4		C		
		3		C		9	A					1			F
				9				7	6	G	C	D	2	E	5
5	1	7					D				B	C	8	F	6
		6	D		C	G		1			F	A	3		
			F		E	8		2		D	5				7
7	F		2		B	3				9	8		A		4
D	C	5	1	6			7	E				G			3
8				2	D				7		G	F	5		1
	4		6		G	5	F		1		3		D	8	B

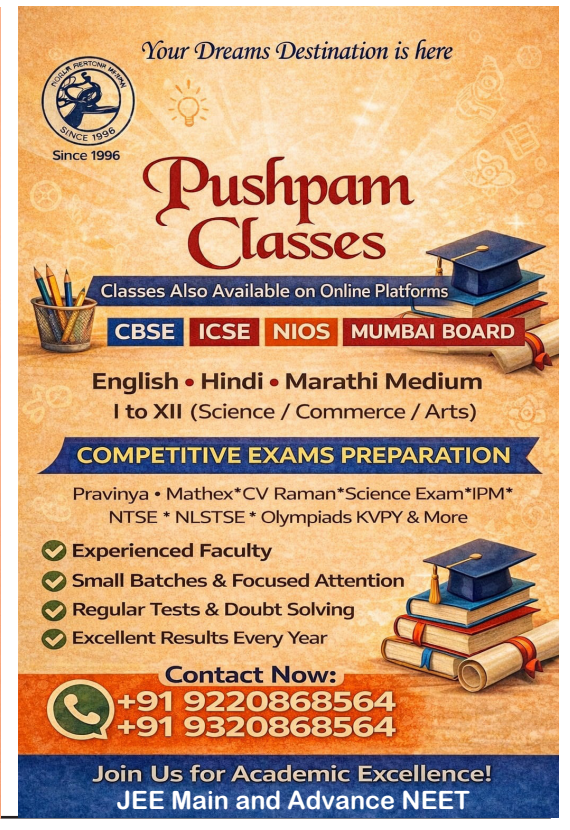

प्यूपिल्स टाइम्स

महाराष्ट्र ने लॉन्च किया भारत का पहला मेनोपॉज क्लीनिक नेटवर्क

महिलाओं के स्वास्थ्य में बड़ा कदम

मुंबई - महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के पहले समर्पित मेनोपॉज क्लीनिक की शुरूआत की है। यह पहल सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में लागू की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मेघना बोरदिकर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम प्रदेश भर में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया गया है।

मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) महिलाओं के जीवन का एक स्वाभाविक जैविक चरण है, जिसमें हार्मोनल परिवर्तन के कारण अनेक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके कारण महिला अनेक बार अनिद्रा, हड्डियों में कमजोरी, मानसिक तनाव, चिंता, हृदय संबंधी जोखिम और जीवन-गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याओं से जूझती है। परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली में इस चरण को कभी गंभीरता से नहीं लिया जाता रहा, जिसके फलस्वरूप बहुत सी महिलाएँ बिना आवश्यक सलाह या उपचार के गुजरती रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन समस्याओं का समाधान निकालते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसके लिए सरकारी अस्पतालों में विशेष मेनोपॉज क्लीनिक स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ महिलाओं को एक ही स्थान पर चिकित्सकीय परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, पोषण संबंधी सलाह, हड्डी एवं हृदय स्वास्थ्य जाँच, तथा अन्य आवश्यक चिकित्सीय सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।

स्वास्थ्य मंत्री मेघना बोरदिकर ने कहा, मेनोपॉज को केवल एक लैंगिक समस्या के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे स्वास्थ्य-संवेदनशील जीवन चरण के रूप में मान्यता मिलनी चाहिये। महाराष्ट्र सरकार इसका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह पहल सम्पूर्ण भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक आदर्श मॉडल बनेगी।

सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से इन सेवाओं का मुफ्त या अत्यंत किफायती प्रदान के लिए चिकित्सा सहायता को अधिक सुलभ बनाता है और स्वास्थ्य असमानता को भी कम करता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शुरूआती दिनों में ही इन क्लीनिकों से हजारों महिलाओं ने लाभ उठाया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस तरह की सेवाओं की समाज में वास्तविक और गहन आवश्यकता थी। महिलाओं ने इस पहल को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाला बताया है। संक्षेप में, महाराष्ट्र सरकार की यह पहल न केवल एक चिकित्सीय आवश्यकता को पहचानती है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य को मानवीय, वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण से संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कदम स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और समानता को मजबूत करते हुए देशभर के लिए एक प्रेरणादायी मॉडल साबित हो सकता है।

- मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल परिवर्तन से महिलाओं के शरीर में स्थिरता प्रभावित होती है। सामान्यतः यह अवस्था 45 से 55 वर्ष के बीच आती है।
- हार्मोनल बदलावों के कारण शारीरिक समस्याएँ जैसे हड्डियों की कमजोरी (ऑस्टियोपोरोसिस), गर्मी के झटके, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द आदि होती हैं।
- मानसिक प्रभाव–अनिद्रा, चिंताएँ, अवसाद और आत्मविश्वास में गिरावट भी आम हैं।
- कई बार सामाजिक संकोच के कारण महिलाएँ इन लक्षणों पर खुलकर चर्चा तक नहीं कर पातीं।
- इन लक्षणों को अक्सर 'उम्र का सामान्य असर' मान लिया जाता है, जिससे महिलाओं को वैज्ञानिक और समयबद्ध चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती। इसका परिणाम यह होता है कि जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है, और कई बार गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ जाते हैं।

क्लीनिक की भूमिका नए मेनोपॉज क्लीनिक महिलाओं को कई प्रकार के समर्थन प्रदान करेंगे

- समग्र स्वास्थ्य परीक्षण
- हार्मोनल संतुलन पर विशेषज्ञ परामर्श
- मानसिक स्वास्थ्य सहायता और काउंसलिंग
- पोषण, योग और जीवनशैली पर मार्गदर्शन
- हड्डी और हृदय स्वास्थ्य की नियमित जाँच

बदलापुर रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन हादसा

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ हादसा

ठाणे - जनवरी 2026 में ठाणे ज़िले के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर एक अत्यंत दर्दनाक और झकझोर देने वाली रेल दुर्घटना सामने आई। सुबह के व्यस्त समय में एक नवविवाहिता महिला लोकल ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने से वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

यह घटना न केवल एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति बनकर सामने आई, बल्कि मुंबई उपनगरीय रेलवे व्यवस्था की यात्री सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर गई।

यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जो बाद में सार्वजनिक रूप से सामने आई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर अत्यधिक भीड़ मौजूद थी. यात्रियों के चढ़ने-उतरने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था. ट्रेन प्लेटफॉर्म से धीमी गति में आगे बढ़ रही थी, जबकि यात्री जबरन चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, वीडियो सामने आने के बाद यह हादसा राज्यव्यापी चर्चा का विषय बन गया।

लोकल ट्रेनों में अत्यधिक भीड़

बदलापुर-अंबरनाथ-कल्याण मार्ग पर चलने वाली लोकल ट्रेनें लंबे समय से क्षमता से कहीं अधिक यात्रियों को ढो रही हैं, विशेषकर पीक आवर्स में। पीक टाइम में अपर्याप्त ट्रेन सेवाएँ कार्यालय समय (सुबह और शाम) में ट्रेनों की संख्या सीमित, यात्रियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण लोग जोखिम उठाकर चलती ट्रेनों में चढ़ने को मजबूर हो जाते हैं।

प्लेटफॉर्म पर अव्यवस्था

सीमित चौड़ाई वाले प्लेटफॉर्म, स्पष्ट भीड़ नियंत्रण व्यवस्था का अभाव, सुरक्षाकर्मियों की कमी जैसी समस्याएँ दुर्घटनाओं की संभावना को और बढ़ा देती हैं।

यात्री सुरक्षा उपायों की कमी

स्वचालित दरवाजों वाली लोकल ट्रेनों की कमी, पर्याप्त चेतावनी प्रणाली का अभाव, और जागरूकता अभियानों की न्यूनता भी इस प्रकार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है।

मुख्य मांगें इस प्रकार हैं—

- पीक आवर्स में अतिरिक्त लोकल ट्रेनों की शुरूआत
- प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग और सुरक्षाकर्मी
- सीसीटीवी निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र
- स्वचालित दरवाजों वाली लोकल ट्रेनों का विस्तार

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और मांगें घटना के बाद स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों, और यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से सख्त और तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि घटना की विस्तृत जांच की जा रही है और यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

बदलापुर एमआयडीसी क्षेत्र में फैक्टरी में भीषण आग

बदलापुर - जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले अंतर्गत बदलापुर स्थित MIDC (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल) औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल/औद्योगिक फैक्टरी में अचानक भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग इतनी तीव्र थी कि कुछ ही समय में फैक्टरी परिसर से उठती लपटें और धुएँ का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे पूरे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

आग लगने का संभावित कारण

प्रारंभिक जांच में आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट, या ज्वलनशील रसायनों के रिसाव को संभावित कारण माना गया है। चूँकि यह इकाई रसायनों के भंडारण/प्रसंस्करण से जुड़ी बताई जा रही है, इसलिए आग ने बेहद तेजी से विकराल रूप ले लिया। हालाँकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम कारण का निर्धारण विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही किया जाएगा।

दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही बदलापुर, अंबरनाथ, और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों से दमकल विभाग की कई गाड़ियाँ तुरंत मौके पर रवाना की गईं। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फैक्टरी परिसर में मौजूद रसायनों के कारण आग बुझाने का कार्य अत्यंत जोखिमपूर्ण था। विशेष फोम और रासायनिक अग्निशमन तकनीकों का उपयोग किया गया।

औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल

इस घटना ने एक बार फिर एमआयडीसी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि-सुरक्षा मानकों, नियमित सुरक्षा ऑडिट, रसायनों के सुरक्षित भंडारण, और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की वास्तविक स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कई औद्योगिक इकाइयाँ अग्नि सुरक्षा उपकरणों का नियमित निरीक्षण नहीं करतीं, कर्मचारियों को आपातकालीन प्रशिक्षण नहीं देतीं, और केवल कागजी अनुपालन तक सीमित रहती हैं।

इस गंभीर घटना के बावजूद किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई, सभी कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रशासन ने इसे त्वरित प्रतिक्रिया और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया।

मौनप्रेम्णः पितुः करुणकथा

एकः पुत्रः आसीत।

सः नित्यं स्वपितरं प्रति अन्तःकरणे असन्तोषभावं वहति स्म। तस्य असन्तोषस्य कारणं न किञ्चिदपि महत आसीत, केवलम एतदेव–पिता अल्पभाषी आसीत। सः न कदाचित पुत्रस्य कृत्येषु स्पष्टतया प्रशंसां प्रकटयति स्म, न च स्नेहपूर्णेन आलिङ्गनेन हर्षं दर्शयति स्म।

पितुः स्वभावः मौनप्रधानः, गम्भीरः, स्थिरचित्तः च आसीत। तस्य निःशब्दता पुत्रस्य हृदये कदाचित शून्यतामिव जनयति स्म।

यदा पुत्रः किञ्चन प्रशंसनीयं कर्म करोति स्म–अध्ययनक्षेत्रे उत्तमान्-परिणामान प्राप्नोति, क्रीडासु विजयम अलभत, अथवा आचार्यैः प्रशस्यते–तदा माता सस्मितं वदति स्म–

'अहो! मम पुत्रः कियत बुद्धिमान,
कियत परिश्रमी च।'
मातुः वाणी माधुर्येण पूर्णा, नेत्रयोः स्नेहः,
हस्तयोः आश्वासनम आसीत।
किन्तु पिता?
सः केवलं दृष्टिं नयति स्म।
मौनमेव तस्य उत्तरम आसीत।

एतत मौनं पुत्रस्य मनसि बहून प्रश्नान जनयति स्म। सः मातरं प्रति पुनः पुनः वदति स्म–

'अम्ब, मे पिता मयि स्नेहं न दर्शयन्ति इव। मम परिश्रमं न पश्यन्ति, मम हर्षं न अनुभवन्ति। यदि ते मयि स्नेहं कुर्वेर्युः, किञ्चित अवश्यं व्यक्तं कुर्युः।'

माता तु केवलं मन्दं स्मित्वा मौनं धारयति स्म। सा जानाति स्म–पितुः स्नेहः वाणीषु न वसति, अपि तु कर्तव्येषु, श्रमे, निःशब्दसेवायां च निवसति।

कालः शनैः शनैः अतीतः।

पुत्रः युवावस्थां प्राप्तवान। अध्ययनसमाप्त्यानन्तरं सः अन्यस्मिन नगरे जीविकां प्राप्तवान। गृहे हर्षः आसीत, किन्तु तेन सह अव्यक्तः विषादः अपि अवसत।

मातुः नेत्रेषु अश्रूणि, हृदये गर्वः;
पितुः मुखे यथापूर्वं गाम्भीर्यम,
अन्तःकरणे तु अगाधा वेदना।

प्रस्थानदिने पिता पुत्रं वाहनस्थानकं पर्यन्तं नीतवान। तत्र जनसमूहः, कोलाहलः, विविधनादाःच आसन। तथापि पिता तेषां मध्ये अपि शान्तः, स्थिरः, अचलदृष्ट्या स्थितवान।

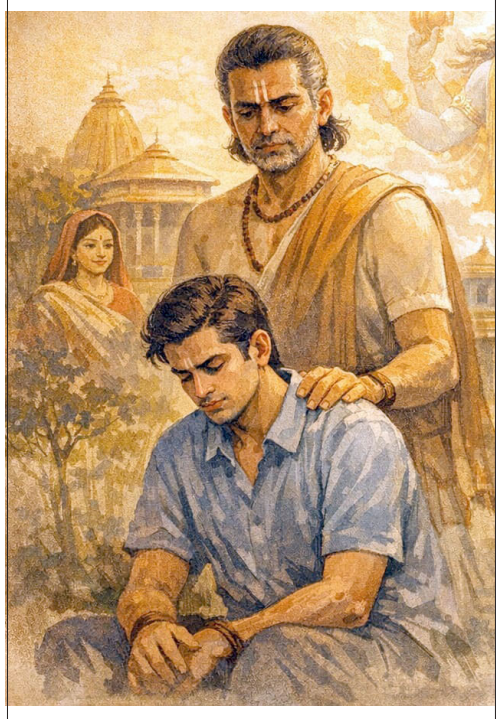

पुत्रस्य अन्तःकरणे किञ्चिद् आशाबीजं प्रस्फुटितम–

'अद्य पिता विशेषं किञ्चित वदिष्यन्ति।
कदाचित मां आलिङ्गिष्यन्ति।
कदाचित हृदयस्थं स्नेहं वाचं रूपेण प्रकाशयिष्यन्ति।'

वाहनम आगच्छत। क्षणाः शेषाः आसन।

पिता केवलम एतावत एव अवदत–

'स्वशरीरस्य यथायोग्यं पालनं कुरु।
यदि कदाचित धनस्य आवश्यकता भवेत, तर्हि सूचय।'

इति।

न अधिकम।

न न्यूनम।

पुत्रः क्षणमात्रं निराशः अभवत। सः वाहनं आरूढः, वातायनसमीपे उपविष्टः। वाहनं शनैः शनैः चलितम। पुत्रः बहिः अपश्यत।

अथ सहसा तस्य दृष्टिः पितरि पतिता।

सः पिता–यः सदा दृढः, कठोरः,
अविचलः इव दृश्यते स्म–
वाहनस्य मार्गपरिवर्तनकाले
स्वस्य जीर्णात विदीर्णात कोषात
पुरातनं वस्त्रखण्डं निष्कास्य
निःशब्दं स्वनेत्रयोः अश्रूणि मार्जयति स्म।
पुत्रस्य हृदयं तदा स्थगितमिव अभवत।
सः अपश्यत–पिता तत्रैव स्थितवान,
यावत वाहनं पूर्णतया
दृष्टिपथात विलुप्तं न अभवत।
तस्मिन क्षणे पुत्रः निःशब्दः अभवत।
तस्य अन्तःकरणे नूतनः बोधः उदितः।
सः अवगच्छत–
पितुः प्रेम शब्देषु न व्यक्तं भवति।
तत न प्रदर्शनस्य विषयः।
तत उत्तरदायित्वस्य, कर्तव्यस्य,
त्यागस्य च निरन्तरप्रवाहः।
माता यदि वाणीभिः स्नेहं दर्शयति,
पिता तु स्वस्वेदेन, स्वश्रमेन, स्वमौनेन
स्वपुत्रस्य भविष्यं निर्माणं करोति।
पिता सागर इव अस्ति–
बहिः शान्तः, निःस्पन्दः;
अन्तः तु सन्तानचिन्तातरङ्गैः
कदापि न विश्रामं प्राप्नोति।

तस्मिन दिने पुत्रः अनुभूतवान–
पिता कदापि प्रेम न्यूनं न अकरोत।
सः केवलं मौनेन प्रेम अकरोत।
एषा कथा न केवलं एकस्य पितुः आख्यानम,
अपि तु सवेर्षां पितणां मौनहृदयस्य आत्मकथैव।
यतः बहवः पितरः
स्वहृदयगतभावान वाणीषु बद्धुं न शक्नुवन्ति।
ते स्वस्नेहं कर्मभिः दर्शयन्ति,
स्वसुखं परित्यज्य अपि सन्तानस्य सुखाय यतन्ते।
पिता स्वस्वप्नान मौनेन त्यजति,
स्वेच्छाः कर्तव्ये विलीनयति,
स्ववेदनां धैर्ये निगृह्णाति।
यदा सन्तानं न विश्रामं लभते,
तदा पिता अपि न विश्रामं लभते।
यदा सन्तानं क्लेशं अनुभवति,
तदा पिता तं क्लेशं
मौनेन स्वहृदये वहति।
तदा पुत्रः ज्ञातवान–
यःकदाचित
'अहं त्वां प्रेम्णा पश्यामि'
इति न वदति,
सः एव प्रतिदिनं तस्य भविष्यस्य भारं
स्वस्कन्धयोः वहति।
अतः पितरः न मौनाः,
ते गभीराः।
ते न असंवेदनशीलाः,
अपि तु अत्यन्तसंवेदनशीलाः।
एवं पितुः मौनं दुर्बलता न,
अपि तु प्रेम्णः परमं स्वरूपम।
इति एषा कथा अस्मान-बोधयति–
सर्वं प्रेम शब्देषु न दृश्यते।
किञ्चित प्रेम मौनेन एव प्रकाशते।

संस्कृतभाषां कथं प्रोत्साहयेम?

संस्कृतभाषा भारतस्य प्राचीनतमा, समृद्धाच भाषा अस्ति।

तस्याः संवर्धनं सवेर्षां कर्तव्यं भवति। निम्नलिखितैः उपायैः संस्कृतभाषा प्रोत्साहयितुं शक्यते –

१. दैनिकजीवने प्रयोगः

प्रतिदिनं सरलसंस्कृतवाक्यानां प्रयोगः करणीयः।

गृहे, विद्यालये, मित्रैः सह च संस्कृते संवादः कर्तव्यः।

२. शिक्षायां विस्तारः

विद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणं रोचकविधिना दातव्यम्।

संभाषण-शिबिराणि आयोजनीयानि।

३. डिजिटलमाध्यमस्य उपयोगः

सामाजिकमाध्यमेषु
संस्कृतविषयकाः
लेखाः, चलचित्राणि, ध्वनिप्रसारणानि च प्रकाशितव्यानि। संस्कृत-अनुप्रयोगाः प्रचारणीयाः।

४. सांस्कृतिककार्यक्रमाः

संस्कृतभाषणम्, नाटकम्, काव्यपाठः, श्लोकगायनम् च आयोजनीयम्।

संस्कृतदिवसस्य उत्सवः आचरनीयः।

५. ग्रन्थपठनम्

सरलसंस्कृतपुस्तकानां पठनम् आरभ्यताम्।

गीता, उपनिषदः, नीतिश्लोकाः अर्थसहितं पठनीयाः।

६. संस्थासहयोगः

संस्कृतविद्यालयानां,
अनुसन्धानकेन्द्राणां च समर्थनम् आवश्यकम्।

सारांशःनित्याभ्यासेन, प्रचारकार्येण, शिक्षणेन च संस्कृतभाषा पुनः लोकप्रियता प्राप्तुं शक्नोति।

संस्कृतं वद – संस्कृतिं रक्ष।

१ फरवरी २०२६ दिना भारतीयसंसदि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण द्वारा वार्षिकः केन्द्रीयबजटः प्रस्तुतः। अस्य बजटस्य मुख्यलक्ष्यं आर्थिकविकासः, आधारभूतसंरचनावृद्धिः, रोजगारसृजनम्, तथा डिजिटल-अर्थव्यवस्थायाः प्रोत्साहनम् इति दृश्यते।

विकासाय आधारसंरचनायाः च बलम्

अस्मिन् बजटे मार्गनिर्माणम्, रेलसेवा, परिवहनव्यवस्था, नगरविकासः च विशेषतया प्रोत्साहिताः। पूंजीव्ययस्य वृद्धिः कृता अस्ति।

विश्लेषणम्: एतेन उद्योगवृद्धिः तथा रोजगारसंधयः वर्धन्ते।

करव्यवस्थायां परिवर्तनम्

मध्यमवर्गस्य कृते कर्रराहत्याः संकेताः दत्ताः।

डिजिटल-लेनदेनस्य प्रोत्साहनम् अपि कृतम्।

विश्लेषणम् : करभारस्य न्यूनता जनव्ययवृद्धये साहाय्यं करिष्यति।

कृषिक्षेत्रस्य उन्नतिः

कृषौ नूतनप्रौद्योगिकी, सिंचनव्यवस्था, भण्डारणसुविधा च विकसितुं योजना कृताः।

विश्लेषणम् : ग्रामीण-अर्थव्यवस्था सुदृढा भविष्यति।

युवा-कौशल-रोजगाराः

युवकानां कौशलविकासाय विशेषकार्यक्रमाः घोषिताः।

स्टार्टअप-उद्योगानां कृते वित्तसहाय्यम् अपि निर्दिष्टम्।

विश्लेषणम् : युवानः स्वावलम्बिनः भविष्यन्ति।

स्वास्थ्य-शिक्षाक्षेत्रे निवेशः

चिकित्सालयानां विस्तारः, चिकित्साशिक्षायाः आसनवृद्धिः, डिजिटल-शिक्षायाः प्रोत्साहनम् च कृतम्।

विश्लेषणम् : मानवसंसाधनस्य दीर्घकालीनविकासः भविष्यति।

प्रौद्योगिकी-क्षेत्रे विशेषबलम्

कृत्रिमबुद्धिमत्ता (अक), डाटाकेन्द्राणि, सेमीकण्डक्टर-उद्योगः च प्रोत्साहिताः।

विश्लेषणम् : भारतदेशः तकनीकीक्षेत्रे अग्रे गन्तुं प्रयतते।

सारांशः

अयं बजटः विकासोन्मुखी, तकनीकीकेन्द्रितः, रोजगारप्रेरकः च अस्ति। यदि योजनानां सम्यक क्रियान्वयनं भवेत्, तर्हि देशस्य अर्थव्यवस्था अधिकं सुदृढा भविष्यति।

मनुष्यविचाराः एव बन्धनमोक्षयोः मूलकारणम्

किं नु वयं सृष्ट्यै स्यामः, उत सृष्टिर्नः कृते अस्ति?

न वयं सृष्ट्यै, न च सृष्टिर्नः कृते। वयं स्वयं एव एषा सृष्टिः स्मः। अस्माकं विचाराः एव घनीभूय भौतिकजगति प्रकटन्ते। यथा वयं चिन्तयामः तथा एव भवामः। अस्माकं उत्थान-पतनयोः कारणं अस्माकं चिन्तनमेव।

कामिनी काञ्चनं च आध्यात्मिकप्रगतौ बाधकौ इति यद् उच्यते, तत सर्वथा असत्यम्। बाधकाः तु लोभः, रागः, द्वेषः, अहंकारश्च एव। अत एव भगवद्गीतायां भगवान् निःस्पृहत्वं, वीतरागत्वं, स्थितप्रज्ञतां च उपदिशति।

यथा कश्चन कामी स्त्रियं कामभावेन पश्यति, श्वा भोजनलोभेन पश्यति, ब्रह्मविद् अनासक्त्या पश्यति, भक्तश्च मातृभावेन पश्यति–तथा दृष्टिरेव बन्धनं वा मोक्षं करोति। स एव साधुः यः निःस्पृहः, वीतरागः, स्थितप्रज्ञश्च अस्ति।

काञ्चनं विना लोकयात्रा न प्रवर्तते। क्षुधा-तृष्णा, शीत-उष्णं, व्याधयः, निवासः–एतेषां सवेर्षां पूर्तये धनम् आवश्यकम्। यथा आध्यात्मिकदारिद्र्यं अभिशापः, तथा भौतिकदारिद्र्यमपि अभिशापः एव।

ईश्वरस्य सृष्टिः न बाधिका; बाधिका तु मनुष्यस्य कल्पना एव। अतः स्वविचारेषु स्वभावेषु च नियन्त्रणं करणीयम्, न तु ईश्वरस्य सृष्टौ दोषारोपणम्।

भौतिकसमृद्धिः आध्यात्मिकसमृद्धेः आधारः अस्ति। शुद्धविचाराः शुद्धभावाश्च एव मनुष्यस्य पतन-उत्थानयोः कारणम्।

अन्ते अहं सर्वेभ्यः धन्यवादं ददामि। भवत्सवेर्षु हृदयस्थं श्रीहरिं नमामि। भवतां कल्याणे एव मम कल्याणं निहितम्।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ शिव शिव शिव शिव शिव

बुद्धिप्रेरणाशक्तिमती

Dr Vandana Mishra
M.A. NET(JRF) PHD

Cambridge to accept CBSE Class 12 for admission

Mumbai: The University of Cambridge has confirmed that it will consider India's CBSE Class 12 qualification for entry to selected undergraduate courses, in a move widely seen as a breakthrough for Indian school students aspiring to study at one of the world's most prestigious universities.

The announcement was made during a high-level visit to India by a senior Cambridge delegation, part of a wider effort to strengthen the institution's academic, research and cultural engagement with the country. University officials said the change would make it easier for bright students educated under the Central Board of Secondary Education system to apply directly, subject to course-specific conditions and high academic performance.

Until now, most Indian applicants to Cambridge have come through international pathways such as A-levels or the International Baccalaureate. The recognition of CBSE marks a shift towards acknowledging national curricula more formally, reflecting both the scale of India's education system and the growing demand among Indian students for access to elite global universities.

School leaders and counsellors have welcomed the development, describing it as a positive signal for students who choose to remain within the Indian board system. Sunayana Awasthi, principal of Kanakia International School, said the announcement would give pupils more confidence about their prospects abroad. "It opens up an additional route for capable students and sends a message that their academic background is being taken seriously," she said.

Among students, the news has generated a mix of excitement and cautious optimism. A Class 11 CBSE student in Delhi said the decision made Cambridge feel more attainable than before. "Earlier, it always seemed that only IB or A-level students had a realistic chance. Now it feels like CBSE students can also aim high, even if the competition will still be tough," the student said.

Speaking during the visit, Cambridge Vice-Chancellor Professor Deborah Prentice said the university was keen to build deeper and more dynamic partnerships in India. She described the move as part of a broader strategy to engage with India's expanding knowledge economy and pool of talented young people. "We are delighted to build on the strong and long-standing links between Cambridge and India," she said. "There is enormous potential for collaboration in research, innovation and education."

A key element of this renewed engagement is the launch of the Cambridge–India Centre for Advanced Studies (CAS). The new centre is intended to act as a focal point for joint research programmes, academic exchange and policy engagement between Cambridge and Indian institutions. University officials said it would support interdisciplinary projects and help connect Cambridge researchers with India's growing innovation ecosystem. Alongside academic initiatives, Cambridge has also taken steps to address the financial barriers that often prevent Indian students from applying to top overseas universities.

Viral Local Train Videos and Social Issues in Badlapur–Ambernath

Badlapur: Viral Social Media Videos In January 2026, several videos related to local train travel in Badlapur and surrounding areas went viral on social media. These videos clearly highlighted unbearable overcrowding, risky travel conditions, and a lack of basic facilities for passengers.

Passenger Safety Concerns The videos and discussions also revealed serious safety issues due to inadequate train frequency, insufficient platform safety measures, and poor crowd management, posing significant risks to daily commuters. Social Inequality and Discrimination Some videos and online discussions indicated that residents of suburban areas like Badlapur face discrimination in matters such as employment, marriage, and social acceptance. This issue goes beyond transportation and reflects underlying social inequality and unequal access to opportunities. Urbanization Challenges The viral content also underscored the limitations of urbanization in the region. Small towns on the outskirts of metropolitan areas often lack proper infrastructure, affecting not only the safety of commuters but also the overall quality of life for residents.

Response from Local Authorities and Citizen Groups Following these incidents and viral videos, local representatives and citizen organizations demanded an increase in local train services, improved connectivity, and stricter measures for balanced urban development. Overall Conclusion Points 4 to 7 of these developments highlight that the Badlapur–Ambernath region is facing serious challenges in:

Industrial safety,
Transport management
Urban planning,
Social structure,

These issues collectively point to urgent attention required from both the authorities and community stakeholders.

A new chapter in economic ties

Education first in a new trade era

India, EU unlock mobility for students, professionals

students and young professionals, the India–European Union Free Trade Agreement is being presented not merely as a pact but as a gateway to classrooms, laboratories and careers across Europe.

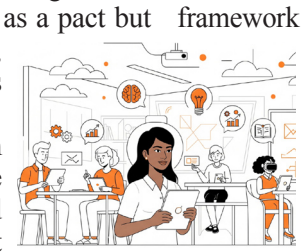

Announced at the 16th India–EU summit by Prime Minister Narendra Modi and European Commission President Ursula von der Leyen, the agreement places mobility, skills and knowledge exchange at the centre of a wider economic partnership. Speaking after the conclusion of negotiations, the Prime Minister underlined the human dimension of the deal. "Alongside this ambitious FTA, we are also creating a new framework for mobility. This will open up new opportunities in the EU for Indian students, workers, and professionals. We have a long-standing and extensive cooperation in science and technology. Today, we have decided to further strengthen these important linkages," Modi said. The emphasis on education and professional movement marks a shift in how trade agreements are framed. Rather than focusing only on tariffs and market access, the India–EU pact links commerce with academic exchange, research cooperation and the global circulation of skilled labour.

Education services form part of the services commitments secured by India under the agreement. Indian service providers will gain predictable access to 144 subsectors in the EU, including education, professional services and information technology. The framework also supports student mobility and post-study work opportunities, an issue of growing importance as Indian students look beyond traditional destinations. European universities already host tens of thousands of Indian students each year, but the new agreement aims to make movement easier and more structured. Officials say the pact strengthens cooperation between higher education institutions and promotes joint research, particularly in science and technology.

Our Cognitive Power

Dr. Arvindsingh Rana
MBBS, DNB (General Surgery)
General & Laparoscopic Surgeon | Coloproctologist FACRSI, FMAS, FIAGES
In a recent statement he said,
Only those who understand the grace of bowing can truly wear the crown.

PUPILS TIMES

Friday, 6 February to 12 February 2026

India-US Trade Deal

Trump finally gets 'peace' endorsement from Modi, PM says US President 'vital for glo

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi's public praise for US President Donald Trump after the trade tariff announcement has given a fresh twist to a long-running debate, with India now appearing to acknowledge Trump's role as a key force for global peace.

Just after the conversation between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, PM recognised that 'President Trump's leadership is vital for global peace, stability, and prosperity. Modi's remarks come at a time when Trump has repeatedly said he deserves global recognition, including a Nobel Peace Prize, for his involvement in defusing conflicts worldwide, including tensions between India and Pakistan.

In a statement on X, PM Modi said: "Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation." "President Trump's leadership is vital for global peace, stability, and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working closely with him to take our partnership to unprecedented heights," PM Modi said on X.

Modi's remarks signal a shift

After speaking to Trump, Prime Minister Modi said the US President's leadership was vital for global peace, stability, and prosperity, and that India fully supports his efforts for peace. The comment stood out because New Delhi has traditionally avoided any comment on President Trump's role in global peace, especially those involving Pakistan.

US President Donald Trump had also invited PM Narendra Modi to be part of the "Board of Peace" for bringing peace to Gaza. But India stayed away from the initiative. By publicly backing Trump's peace credentials, India has, for the first time, appeared to align itself with Trump's own narrative of being a global peace broker.

CBSE Launches Psycho-Social Counselling Support to Help Students Cope with Exam Stress

New Delhi: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has launched Psycho-Social Counselling Support for Students to help Class 10 and Class 12 students deal with examination-related stress and mental pressure. The initiative is being seen as a significant step towards strengthening students' mental health and emotional well-being.

According to CBSE, the first phase of the free counselling services will continue until June 1 this year. During this period, students appearing for the board examinations will receive professional psychological and emotional guidance from trained experts.

The primary objective of this initiative is to reduce anxiety, fear, and stress commonly experienced by students during examinations, enabling them to approach the board exams beginning from February 17 with greater confidence, emotional balance, and mental clarity.

CBSE officials stated that in today's highly competitive academic environment, examination stress has emerged as a serious concern. This counselling support aims not only to assist students in managing exam pressure but also to help them understand their emotions and develop a positive and resilient mindset. Through this psycho-social counselling programme, students will receive guidance on stress management, time management, confidence building, and emotional stability. The Board believes that mentally healthy students are better equipped to perform well academically.

Education experts have welcomed CBSE's initiative, describing it as a timely and necessary measure that supports students' holistic development and promotes mental well-being alongside academic excellence.

President's Address 2026: Policy, Vision and the Road to a Developed India

New Delhi: Today In India's parliamentary democratic tradition, the President's Address holds a position of great constitutional significance. It is not merely a ceremonial statement, but an official document outlining the policy direction, priorities, and future roadmap of the Union Government. In this context, President Droupadi Murmu addressed the joint sitting of both Houses of Parliament at the commencement of the Budget Session 2026–27.

The Address was delivered under Article 87 of the Constitution, which mandates that at the beginning of each annual session of Parliament, the policies and programmes of the government shall be placed before the Legislature. Vision of a Developed India In her latest Address, President Droupadi Murmu described the year 2026 as a decisive milestone on India's journey towards becoming a "Developed India." She stated that the government's objective is not limited to economic growth alone, but extends to building a strong nation through social justice, inclusive development, and institutional strengthening.

The President emphasized that development acquires true meaning only when its benefits reach the last person standing in society, reflecting the core spirit of Indian democracy.

Economic Progress and Infrastructure The Address elaborated on the strength of India's economy. The President noted that India is currently among the fastest-growing major economies in the world. She identified infrastructure development, modern transport networks, digital connectivity, and expansion of the manufacturing sector as the backbone of economic progress. Structural reforms, an investment-friendly environment, and the "Atmanirbhar Bharat" initiative were highlighted as foundations of economic stability and long-term growth.

Social Justice and Inclusive Development Social justice was underscored as a central priority of the government. The President stated that the poor, farmers, women, youth, and marginalized sections remain at the core of government policies.

She reiterated the government's commitment to empowering vulnerable sections through initiatives related to health, housing, sanitation, nutrition, and social security, with the aim of ensuring a dignified life for all citizens. Special Emphasis on Women Empowerment President Droupadi Murmu placed special emphasis on women empowerment, describing it as an essential condition for national development.

PUPILS TIMES

Core Committee

Anurag Shukla
Chief Editor

Shivprakash Pandey
Chief Publisher

Vikas Maurya
Co Publisher

Address: Shop No. 3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503
Contact: 9004331751
Web: pupilstimes.com

(The editor does not necessarily agree with the news, articles, and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai courts.)

Printed, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **JAGRUTI PRINTERS,** BYCULLA SERVICE INDUSTRIAL ESTATE 1ST FLOOR, B-101, D.K. CROSS MARG, NEAR RANIBUAG, MUMBAI, MAHARASHTRA - 400027. **Published at:** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA)
Editor - **ANIL MISRA** Mob: **92208 68564** **Email:** anilmisrapc@gmail.com **PRGI. No.: MHMUL/25/A2419**